



गोल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम — महारात्र कंपनी)

GAIL (India) Limited

(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गोल भवन,
16 भीकाईजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, भारत
GAIL BHAWAN,
16 BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110066, INDIA
फोन/PHONE: +91 11 26182955
फैक्स/FAX: +91 11 26185941
ई-मेल/E-mail: info@gail.co.in

एनडी/गोल/सेक्ट/2021

20.12.2021

<p>1. लिस्टिंग अनुपालन</p> <p>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड</p> <p>एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुली कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400 051</p> <p>स्क्रिप्ट कोड: गोल-ईक्यू</p>	<p>2. लिस्टिंग अनुपालन</p> <p>बीएसई लिमिटेड</p> <p>फ्लोर 1, फिरोज़ जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001</p> <p>स्क्रिप्ट कोड: 532155</p>
--	--

विषय: न्यूज़ पेपर प्रकाशन- शेयरधारकों हेतु सूचना जिनके शेयर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम 2016 ("नियम") के अनुरूप निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आई. ई. पी. एफ) में अंतरित किए जा रहे हैं।

प्रिय महोदय/महोदया,

यह सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 30 के अनुपालन में है।

इस संदर्भ में, कृपया अनुलग्नक प्राप्त करें।

उपर्युक्त आपकी सूचना एवं रिकॉर्ड हेतु है।

धन्यवाद,

भवदीय,

अमित शर्मा

(ए के श्वार)

कंपनी सचिव

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

सरकार सही वक्त पर इस मुद्दे पर व्यापक राय बनाने की कार्यवाही कर सकती है शुरू राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने के लिए फिर से प्रयास तेज

हिन्दुस्तान खास

नई दिल्ली | शायां सुमन

देशभर के उच्च न्यायालयों में खाली पड़ों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं आ रही है। पिछले दस वर्षों से यह अंकड़ा 400 से ऊपर का बना हुआ है, जो खाली पड़ों का लगभग 43 प्रतिशत है। ऐसे में न्यायिक नियुक्ति आयोग को फिर से लाने की नियुक्ति न्यायालिका पर ही नहीं छोड़ी जा सकती।

न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की मांग से सरकार भी सहमत है, पर उसकी तरफ से कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई नहीं है। सरकार के अनुसार, सरकारी वक्त वर्षों (संभवतः यूपी चुनाव के बाद) इस मुद्दे पर व्यापक राय बनाने की कार्यवाही शुरू कर सकती है। कानून मंत्री किसेवा रिजिस्ट्रेशन कोहा है कि उनके पास एनजेसी (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) को फिर से लाने के लिए पत्र आ रहे हैं। इसमें उच्च न्यायालिका के पूर्व जज, बार लीडर, एनजीसी शामिल हैं। सभी एक



400

मौजूदा व्यवस्था

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए शीर्ष वक्तव्यों की संीकृत जजों की गोपनीय रूप से बहुमत उनकी ही रहे।

विधाया एनजेसी
एप्रिल, 2014
देश के मुख्य न्यायाधीश आयोग की अध्यक्ष होते। सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ वक्तव्य, जज, कानून मंत्री और दो विशेष न्यायाधीश (जिनका चयन मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री और विषयक को नेता करते) आयोग का एक खत्रतंत्र संविधालय भी होता।

शिकायत तंत्र भी था
इस कानून में जजों की शिकायत के लिए तंत्र भी है, जिसे आयोग ही देखता और जाच करता और संसद में महाभियोग बनाता जैसे जटिल उपाय को नहीं अपनाना पड़ता।

अग्री शिकायत तंत्र नहीं
जजों की शिकायत के लिए फिरहाल काँड़े तंत्र नहीं है। शिकायत अपने पार्ट को जजों की एक आतिक कमटी बनाता है, जो गोपनीय जाच करती है, जाच को कभी साधनजनक नहीं किया जाता।

सुधे से न्यायिक आयोग विधेयक फिर से लाने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि हम मानों के संसदेशाली हैं, लेकिन कोई वाला नहीं कर रहे हैं।

संसद ने पूर्ण सहमति से बनाया था

कानून: 2014 में लाया गया एनजेसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में नियस्त कर दिया था। इससे विधायिका में चिता व्यक्त की गई थी, जोकि वह संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित हुआ था और इसे देश के 50 %

विधानसभाओं ने अपनी मंजूरी दी थी। कई पार्टियों ने कहा यहा समस्ति से पारित कानून को दो रायवाचिका की सर्वसम्मति में दखल है। इतना ही नहीं कोर्ट ने शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन भी किया है। यदि कानून के किसी भाग से दिक्कत थी तो उसे नियस्त किया जा सकता था, पूरा कानून नहीं। कोर्ट ने कानून का आयोग भी न होने दिया। कोर्ट ने कानून का आयोग भी न होने दिया। प्रयोग के बाद उसके गुण-दोष देखकर उसे नियस्त किया जा सकता था।

राहुल ने फिर बताया हिंदू-हिंदुत्व का फर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग हिंदूत्व में यकीन रखते हैं उनका मानना है कि सभी भारतीयों का डीएनए पक्का समान है लेकिन हिंदू मानने हैं कि हर आदमी का डीएनए अलग और अनन्य होता है।

कांग्रेस नेता जिप्पी रायटीय स्वयंसेवक (आएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत की उपायिका के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए 40,000 साल से एक समान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, 'हिंदू मानने हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग और अनन्य होता है।'

सिद्ध पर कांग्रेस को बांटने का आरोप

चंडीगढ़: पंजाब सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने रविवार को प्रेस कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्ध को एक खुदार्ज राजनीतिज्ञ करार दिया। उन्होंने सिद्ध पर जंजाब को बांटने का आरोप भी लगाया।

राणा ने कहा कि सिद्ध सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए एक गोपनीय विधायिका बनने के लिए बहुत मानवीय है। उन्होंने पार्टी के सचेव पारंपरिक नेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिससे मध्येष्ठ पैदा हुए। राणा ने कहा, सिद्ध जितनी जल्दी कांग्रेस छोड़ते हैं, पार्टी के लिए उतना ही अच्छा होगा। उन्होंने पार्टी को काफी गहरा नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने जल जीवन मिशन में टेंडर घोटाला, मधिर निर्माण में जमीन घोटाला और कोरोना महामारी के दोरान विभिन्न योजनाओं में ग्राम्यजन का बायात किया।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी तक लेकिन सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

आप सांसद ने कहा कि प्रदेश में अपाध चरम सीमा पर पहुंच चुका है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

आप सांसद ने कहा कि प्रदेश में अपाध चरम सीमा पर पहुंच चुका है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में लोगों को सुपुत्र बिजली, मुक्त स्वस्थ सेवा, मुक्त पानी, बेहतर और उन्नत नियाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वारों पर खरीदी नहीं उत्तर पाइ है।